बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 16

व्यापारिक चूक

अमेरिकी प्रशासन ने भारत और तुर्की से होने वाले आयात को अपनी व्यापक वरीयता व्यवस्था (जीएसपी) से बाहर करने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के तहत चुनिंदा वस्तुओं को शून्य शुल्क पर अमेरिका में आयात किया जाता रहा है। भारत इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभार्थी है और उसे करीब 560 करोड़ डॉलर मूल्य का आयात लाभ होता है। यह पहले से तनावग्रस्त भारतीय निर्यातकों के लिए परेशान करने वाली सूचना है। इसे लेकर भारतीय प्रशासन का आशावादी रवैया भी गलत है। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया में होने वाली रियायत की राशि सालाना 20 करोड़ डॉलर से भी कम थी इसलिए निर्यातक अधिक प्रभावित नहीं होंगे। भारत-अमेरिका व्यापार रिश्तों को यह एक बड़ा झटका है और भारत की प्रतिक्रिया बहुत हल्की है। भारत के कई निर्यातकों को इससे मामूली ही सही प्रतिस्पर्धी लाभ हासिल था। ऐसे में यह बदलाव सरकार के अनुमान से कहीं अधिक नुकसानदेह हो सकता है।

यह बात भी ध्यान देने लायक है कि इसका भारत और अमेरिका के आर्थिक रिश्तों पर क्या असर होगा। भारत और अमेरिका के कारोबार में भारत के पास मामूली व्यापार अधिशेष है। यह करीब 230 करोड़ डॉलर मूल्य का है। मौजूदा अमेरिकी प्रशासन के संरक्षणवादी रुख को देखें तो यह तनाव इतना नहीं बढ़ने देना चाहिए था कि भारत को सन 1970 के दशक से मिल रहा लाभ समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं है कि भारत ने रियायत नहीं दी है। उदाहरण के लिए अमेरिका से होने वाले मोटर साइकिल आयात पर शुल्क कम किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप बार-बार आग्रह कर रहे थे कि हार्ली डेविडसन मोटर साइकिल पर से शुल्क कम किया जाए। यह मोटर साइकिल अमेरिका के ऐसे प्रांत में बनती है जो चुनावी दृष्टि से अहम है। यह स्पष्ट है कि भारत ने इस अवसर का लाभ अमेरिका के साथ अधिक एकीकृत आर्थिक मसलों को प्रभावी बनाने के लिए नहीं किया। फिलहाल जिन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचेगा, उनमें रसायन एवं अभियांत्रिकी शामिल हैं। यह वह विनिर्माण क्षेत्र है जिसका निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि देश में रोजगार तैयार हो सकें।

दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय कारोबारी प्रतिष्ठान देश के हित के मामलों में भी अदूरदर्शी है। इन हालात के लिए देश में हाल में उठाए गए लोकलुभावन कदमों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में बने चिकित्सा उपकरणों, खासतौर पर कार्डियक स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण में काम आने वाले उपकरणों पर नियंत्रण थोपने से अमेरिका नाखुश है। दुख की बात यह है कि इस क्षेत्र में मूल्य नियंत्रण से भारतीय मरीजों को भी कोई लाभ नहीं हुआ है क्योंकि अस्पताल आसानी से बढ़ी लागत को कहीं न कहीं समायोजित कर देंगे। भारत यह कहता रहा है कि धार्मिक वजहों से अमेरिका से दुग्ध उत्पादों का आयात नहीं किया जाता। इसकी एक वजह यह है कि अमेरिका ने बोवाइन सोमाटोट्रोपिन पर प्रतिबंध नहीं लगाया है जो पशुओं की पीयूष ग्रंथि से बनता है। यह डेरी फार्मिंग में पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है। इस क्षेत्र में हम किसी समझौते पर क्यों नहीं पहुंचे यह भी स्पष्ट नहीं है। भारत के विकल्प सीमित हैं। उदाहरण के लिए उसने 29 अमेरिकी वस्तुओं पर प्रतिरोध स्वरूप 23.5 करोड़ डॉलर मूल्य का शुल्क लगाया था लेकिन अब तक वह इस उम्मीद में छह बार इसका क्रियान्वयन टाल चुका है कि अमेरिका के साथ समझौता हो जाएगा। ऐसी कवायद बेमानी हैं। विश्व व्यापार जगत में जब चीन पर दबाव बढ़ रहा है और व्यापारिक नेटवर्क निरंतर बदल रहे हैं तो भारत को इसका लाभ लेना चाहिए। इसके बजाय सरकार संभावित व्यापारिक लाभ की अनदेखी कर रही है।

अजय मोहंती

एशिया और भारत के लिए अहम है सऊदी अरब

अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच सऊदी अरब ने एशिया में चीन और भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की पहल की है। देश बदलती परिस्थितियों का लाभ किस प्रकार उठाता है। बता रहे हैं **हर्ष वी पंत**

पिछले दिनों भारत की यात्रा पर आए सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) को लेकर हमारे देश में होने वाली चर्चा मोटे तौर पर इस बात पर केंद्रित रही कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को लेकर संतुलन कायम करने की कोशिश की। उनकी यह यात्रा पुलवामा हमले के तुरंत बाद हुई थी और यही वह वक्त था जब भारत पाकिस्तान को लेकर अपना रुख सख्त कर रहा था। परंतु इसके अलावा भी इस यात्रा के व्यापक भू सामरिक महत्त्व को हमें समझना होगा। सऊदी अरब के रिश्ते अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ तेजी से खराब हो रहे हैं और एमबीएस की कोशिश यह संकेत देने की थी कि उनका देश चीन और भारत जैसे एशियाई देशों के साथ तालमेल बेहतर करने में लगा है। वह दुनिया को यह भी दिखाना चाहते थे कि वह इतने अलग-थलग भी नहीं हैं जितना कि समझा जा रहा है। यह उनकी सामरिक नीति है जो एमबीएस की आलोचना करने वालों को यह बताती है कि वह वैश्विक स्तर पर अभी भी एक कामयाब नेता हैं और वैश्विक शक्ति से जुड़े अहम राष्ट्रों में उनका काफी असर है।

पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के रिश्ते काफी पुराने हैं जिन्हें उसने नया दम दिया। यह एक ऐसी साझेदारी है जिसमें सऊदी अरब पाकिस्तान को आर्थिक बुनियादी मदद पहुंचाता रहा है और बदले में उसे और वहां के शाही परिवार को पाकिस्तानी सेना का संरक्षण मिलता है। जैसा कि इमरान खान ने हाल ही में कहा था, 'हमने हमेशा कहा है कि अगर इस्लाम के पवित्र शहरों को कोई खतरा उत्पन्न हुआ तो पाकिस्तान उन्हें बचाने का पूरा प्रयास करेगा।' हाल के महीनों में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 600 करोड़ डॉलर का जो ऋण दिया है वह भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से बातचीत की दृष्टि से बहुत अहम रहा है। अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान एमबीएस ने 1,000 करोड़ डॉलर के समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते ग्वादर में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए किए गए। ग्वादर चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर पर स्थित है और वह एक बेल्ट, एक रोड पहल की दृष्टि से भी बेहतर है। यह परियोजना सऊदी कंपनी को बलूचिस्तान प्रांत में जगह देगी जहां से आवश्यकता पड़ने पर ईरान को निशाना बनाया जा सकता है। साथ ही उसे चीन के साथ साझेदारी विकसित करने का अवसर भी मिलेगा। इसके चकित करने वाली कोई बात नहीं है कि चीन ने सीपीईसी में सऊदी अरब के प्रवेश की सराहना की है। यह परियोजना कई मोर्चों पर दिक्कत का सामना कर रही है।

चीन सऊदी अरब का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। दोनों के बीच 6,330 करोड़ डॉलर का कारोबार होता है। वर्ष 2017 में जब सऊदी शाह सलमान ने चीन की यात्रा की थी तो दोनों देशों ने 6,500 करोड़ डॉलर के सौदों पर हस्ताक्षर किए थे। इस दौरान पूरा ध्यान ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर था। एमबीएस की यात्रा में यह संकेत निहित था कि वह पश्चिम की बढ़ती चिंताओं के बावजूद साम्राज्य का अहम हिस्सा हैं। चीन की बेल्ट रोड पहल के अनुरूप सऊदी अरब ने लाल सागर के तटवर्ती इलाके में आर्थिक क्षेत्र विकसित करने की बात कही है। इस काम के पूरा होने तक सऊदी अरब की ओर से इसमें 50,000 करोड़ डॉलर का निवेश किया जाएगा। सऊदी अरब चीनी भाषा को अपने स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल करने पर सहमत हो गया है।

इस यात्रा का सबसे अहम पहलू था एमबीएस द्वारा चीन में चल रहे मुस्लिमों के यातना शिविरों का बचाव। उन्होंने कहा था कि चीन को यह अधिकार है कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आतंकवाद विरोधी और चरमपंथ विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे। इस महीने के आरंभ में तुर्की की रेसेप तैयप एर्डोगन के नेतृत्व वाली सरकार ने इस धरपकड़ को मानवता के लिए शर्मनाक बताया था। उसने इन शिविरों में कथित अत्याचार और राजनीतिक समझ बदलने के प्रयासों की भी निंदा की थी। इस बीच चीन पश्चिम एशिया के दो प्रतिद्वंद्वियों सऊदी अरब और ईरान के बीच संतुलन कायम करने की कोशिश में लगा हुआ है। एमबीएस की यात्रा के ऐन पहले ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ चीन आए थे। म्युनिख सुरक्षा सम्मेलन में भी चीन ने जरीफ के भाषण की तारीफ की थी। चीन के स्टेट काउंसिलर वांग यी ने कहा, 'मैंने टेलीविजन पर देखा कि आपने सम्मेलन में किस तरह खुलकर ईरान के अधिकारों का बचाव किया। मुझे लगता है कि लाखों चीनी नागरिकों ने भी देखा होगा कि आपने क्या कहा और अब आप चीन में एक चर्चित हस्ती हैं।' सऊदी अरब और ईरान के भूराजनैतिक आकलन में चीन की महत्ता बढ़ रही है और शिनच्यांग प्रांत में मुस्लिमों पर अत्याचार के मामले में दोनों देशों की खामोशी काफी कुछ कह रही है।

भारत में भी एमबीएस का ध्यान आर्थिक और व्यापारिक मसलों पर था और उन्होंने अगले कुछ वर्ष में 10,000 करोड़ डॉलर के निवेश की बात कही। अरैमको और अबू धाबी नैशनल ऑयल कंपनी महाराष्ट्र में रत्नागिरि तेल रिफाइनरी की स्थापना में 440 करोड़ डॉलर का निवेश कर रही हैं। एसएबीआईसी भी भारत में पेट्रोकेमिकल संयंत्र में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने वाली है। दोनों देश सौर ऊर्जा और उपग्रह तकनीक के क्षेत्र में भी मिलकर काम करने वाले हैं। देश का 20 फीसदी तेल आयात सऊदी अरब से होता है जबकि देश के करीब 27 लाख लोग वहां रहकर काम करते हैं। परंतु एमबीएस की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों का संयुक्त दस्तावेज महत्त्वपूर्ण होकर उभरा जिसमें सऊदी अरब ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया।

एमबीएस की भारत यात्रा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका में सऊदी अरब को लेकर माहौल बेहद खराब है। सऊदी अरब ने उसे साफ संकेत दिया है कि वह अपने साझेदार बदल सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट के स्तंभकार जमाल खशोगी की क्रूर हत्या के बाद अमेरिका की नजरें एमबीएस पर वैसे ही टेढ़ी हैं। यमन में भी हालात खराब हैं। एक ओर जहां ट्रंप प्रशासन सऊदी अरब को परमाणु तकनीक बेचने पर विचार कर रहा है, वहीं अमेरिकी सीनेट यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि इस मसले पर अंतिम निर्णय उसका हो। यमन में बढ़ता तनाव भी पिछले कुछ समय से प्रत्यक्ष है।

ऐसे में सऊदी अरब का एशिया की ओर रुख करना समझ में आता है। इन बदलते हालात में भारत की क्या भूमिका होगी यह अभी देखा जाना होगा।

(लेखक किंग्स कॉलेज, लंदन के रक्षा अध्ययन विभाग में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्राचार्य हैं।)

राजकोषीय मजबूती की कोशिशों से पूंजीगत व्यय पर आशंका

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

अगर सरकार संशोधित राजकोषीय घाटा लक्ष्य हासिल करना चाहती है तो व्यय पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सरकार के राजस्व व्यय में तो अधिक गुंजाइश नहीं दिखती है।

वर्ष 2018-19 के लिए अपने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.4 फीसदी तक सीमित रखने के संशोधित लक्ष्य को क्या केंद्र सरकार हासिल कर पाएगी? मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के बारे में महालेखा नियंत्रक की तरफ से हाल ही में जारी आंकड़े देखें तो संदेह पैदा होना लाजिमी है।

इन आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2018-जनवरी 2019 के दौरान राजकोषीय घाटा पूरे वित्त वर्ष के लिए अनुमानित लक्ष्य का 121 फीसदी हो चुका है। गत 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में दी गई जानकारी से पता चलता है कि राजकोषीय घाटा इस वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में ही 7.71 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। इस वजह से 6.34 लाख करोड़ रुपये का संशोधित लक्ष्य पाने के लिए सरकार को बाकी दो महीनों में 1.37 लाख करोड़ रुपये के राजकोषीय अधिशेष की जरूरत पड़ेगी।

सरकार के लिए ऐसा कर पाना कितना मुश्किल होगा? आंकड़े खुद ही इसकी गवाही देते हैं। इसके लिए राजस्व प्राप्ति के मासिक रुझान को समझना मददगार होगा। समूचे बजट आकार का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा राजस्व प्राप्ति का ही होता है। वर्ष 2017-18 के पहले 10 महीनों में कुल राजस्व प्राप्तियों का करीब 76 फीसदी हिस्सा संग्रह हुआ था। दूसरे शब्दों में, कुल राजस्व प्राप्तियों का 24 फीसदी हिस्सा वित्त वर्ष के अंतिम दो महीनों में आया। इसी तरह कुल राजस्व प्राप्तियों में अहम स्थान रखने वाले केंद्रीय शुद्ध कर राजस्व के मामले में 2017-18 का करीब 22 फीसदी हिस्सा फरवरी और मार्च महीने में ही आया।

एक पल के लिए यह मान लें कि वित्त वर्ष 2018-19 में भी आखिरी दो महीने पिछले साल की ही तरह राजस्व जुटाने में सफल रहेंगे। लेकिन ऐसा होने पर भी समस्या यह है कि संशोधित राजस्व प्राप्ति लक्ष्य से 1.33 लाख करोड़ रुपये कम ही रह जाएगी। इस कमी की भरपाई केवल तभी हो सकती है जब सरकार को वित्त वर्ष के अंतिम दो महीनों में पूरे साल की राजस्व प्राप्ति का 32 फीसदी हिस्सा मिल जाए। लेकिन ऐसा हो पाने की संभावना लगभग नगण्य है।

फिर सरकार के पास क्या चारा रह जाता है? पूंजी के मोर्चे पर विनिवेश प्राप्तियां अच्छी हालत में हैं। हालांकि आलोचक हमेशा ही विनिवेश प्राप्तियों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाएंगे क्योंकि यह सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए संसाधन स्थानांतरित करने का जरिया भर बनकर रह गया है। जनवरी के अंत तक विनिवेश प्राप्तियां 35,606 करोड़ रुपये तक ही पहुंच पाई थीं जबकि वित्त वर्ष के लिए 80,000 करोड़ रुपये प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। फरवरी में 20,867 करोड़ रुपये का विनिवेश कार्य पूरा किया गया जिसके बाद इस मद में कुल प्राप्तियां 56,473 करोड़ रुपये हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि अकेले मार्च महीने में 23,527 करोड़ रुपये की विनिवेश प्राप्ति जरूरी होगी। वैसे 2017-18 के आंकड़े देखें तो सरकार के लिए ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। अकेले फरवरी-मार्च 2018 में 44,652 करोड़ रुपये की विनिवेश प्राप्तियां हुई थीं।

इस तरह अगर सरकार संशोधित राजकोषीय घाटा लक्ष्य हासिल करना चाहती है तो व्यय पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सरकार के राजस्व व्यय में तो अधिक गुंजाइश नहीं दिखती है। बड़ी सब्सिडी के मामले में हमेशा ही स्थगन की संभावना रहती है लेकिन इस समय बहुत कम सुधार की गुंजाइश दिख रही है। चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में बड़ी सब्सिडी के मद में व्यय 2.59 लाख करोड़ रुपये और संशोधित अनुमानों के मुताबिक समूचे वित्त वर्ष का व्यय 2.66 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यानी आखिरी दो महीनों में सब्सिडी वितरण में शायद ही कोई गतिविधि होगी क्योंकि सरकार ने व्यय मद को पहले ही संकुचित कर दिया है।

फिर सरकार को इस स्थिति से उबारने का काम पूंजीगत व्यय ही कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो वह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। पूंजीगत व्यय की नकेल कसने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। इस तरह जनवरी 2019 के अंत तक सरकार का पूंजीगत व्यय 2.29 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। अंतरिम बजट में दिए गए संशोधित अनुमानों के मुताबिक पूरे साल के लिए यह आंकड़ा 3.16 लाख करोड़ रुपये रहेगा। ऐसे में पूरी आशंका है कि सरकार वित्त वर्ष के आखिरी दो महीनों में आवंटित राशि में से बाकी 87,000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी।

इसकी संभावना भी है कि सरकार पूंजीगत व्यय के तहत खर्च न की जा सकी समूची रकम का इस्तेमाल राजस्व प्राप्ति में 1.33 लाख करोड़ रुपये की कमी को पूरा करने के लिए करे। ध्यान रखें कि सरकार ने पिछले साल असल में मार्च 2018 में 33,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय वापस ले लिया था। इस तरह सरकार का पूंजीगत व्यय फरवरी 2018 तक 2.97 लाख करोड़ रुपये था लेकिन मार्च 2018 में यह घटकर 2.64 लाख करोड़ रुपये हो गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2018-19 में 190 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने से भी सरकार को राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर 6,000 करोड़ रुपये की सुरक्षा मिलेगी। अधिक कर राजस्व जुटाने और पूंजीगत व्यय में कटौती के लिए अतिरिक्त प्रयासों से सरकार राजकोषीय घाटे के संशोधित लक्ष्य को हासिल करने की उम्मीद कर सकती है। लेकिन आलोचक हमेशा ही राजकोषीय मजबूती की ऐसी कोशिशों पर सवाल उठाते रहते हैं।

कानाफूसी

हिंदी में ट्वीट

सोमवार को जब पाकिस्तान के सत्ताधारी राजनीतिक दल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से जब हिंदी में ट्वीट किया गया तो न केवल भारत बल्कि पाकिस्तान में भी लोग चकित रह गए। पार्टी ने अपने ट्वीट में देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान की वह प्रतिक्रिया प्रस्तुत की जो उन्होंने उनके लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग करने पर प्रकट की थी। ट्वीट में कहा गया था कि वह खुद को इस पुरस्कार का दावेदार नहीं मानते और यह पुरस्कार उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो कश्मीरी लोगों की इच्छा के मुताबिक कश्मीर समस्या को हल कर सके और उपमहाद्वीप में शांति और मानव विकास सुनिश्चित कर सके। ट्विटर पर लोग इस बात पर आश्चर्य जताते देखे गए कि पाकिस्तान में इतनी शुद्ध हिंदी कौन लिख रहा है।

तमिलनाडु में नए चेहरे

आगामी लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में नई पीढ़ी के कई नेता अपने करियर की शुरुआत करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पलनिस्वामी के बेटे मिथुन कुमार और उद्योग मंत्री एम सी संपत के बेटे के नाम पर आवेदन भी करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पनीरसेल्वम के बेटे पी रवींद्रनाथ कुमार भी अपना आवेदन प्रस्तुत करने का मन बना रहे हैं। जो अन्य नेता अपने करीबियों के लिए सीट चाहते हैं उनके नाम हैं-मत्स्यपालन मंत्री डी जयकुमार, विधि मंत्री सीवी षणमुगम और नगर प्रशासन मंत्री एस पी वेलुमणि। अभिनेता उदयनिधि स्टालिन के समर्थकों ने उनके पिता और द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन से मांग की है कि उनको तिरुवरूर से उम्मीदवार बनाया जाए। सुनने में आया है कि द्रमुक के एक अन्य नेता और पार्टी के कोषाध्यक्ष एस दुरईमुरुगन ने अपने बेटे कथिर आनंद के लिए वेल्लोर से टिकट मांगा है। इनके अलावा देशीय मुरपोक्कु द्रविड़ कषगम के नेता विजयकांत के बेटे विजय प्रभाकरण भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं।

आपका पक्ष

ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में भी रसोई गैस

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सभी घरों में रसोई गैस कनेक्शन देने की योजना है। घरों में धुआं रहित रसोई देने की सरकार की इस महत्त्वाकांक्षी योजना से महिलाओं को काफी फायदा होगा। उन्हें धुएं के कारण होने वाली सांस संबंधी बीमारी नहीं होगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2015 तक देश में करीब 14.8 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता थे। वर्तमान में यह संख्या बढ़कर करीब 26.16 करोड़ हो गई है। पिछले तीन वर्षों में एलपीजी उपभोक्ताओं में करीब दोगुना वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के कारण सरकार पर एलपीजी पर दिए जाने वाली सब्सिडी का बोझ भी पिछले तीन वर्षों में करीब दोगुना बढ़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एलपीजी के कुल उपभोक्ताओं में से करीब 24.27 करोड़ उपभोक्ता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (डीबीटीएल) के तहत

आते हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का नाम बदल कर अब पहल योजना कर दिया गया है। सरकार ने सब्सिडी के लिए आय की सीमा तय की है और 10 लाख रुपये सालाना पारिवारिक आय से कम वाले को ही सब्सिडी मिलेगी। किसी परिवार में कमाने वाले सभी सदस्यों की आय अगर 10 लाख रुपये से अधिक है तो उस परिवार को गैस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। सरकार ने गिव इट अप योजना बनाई है जिसके तहत कोई उपभोक्ता इच्छानुसार सब्सिडी छोड़ सकता है। बहरहाल मई 2016 में शुरू हुई उज्ज्वला योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में भी घरों में रसोई गैस जल रही है। पहले किसी के घर में रसोई गैस होना प्रतिष्ठा का विषय होता था। वहीं यह भी अवधारणा बनी थी कि यह फिजूलखर्च के लिए है, क्योंकि रसोई घर में कोयले या लकड़ी के चूल्हे में खाना पकाया जाता था। लेकिन आज लगभग सभी घरों में रसोई गैस पहुंचने से लोगों में इसकी उपयोगिता की समझ बढ़ी है तथा इसके फायदे नजर आने लगे हैं।

अंकिता कुमारी, नोएडा

पिछले तीन वर्षों में घरेलू रसोई गैस कनेक्शन में करीब दोगुनी वृद्धि हुई है

किफायती मकानों की परिभाषा सरल हो

जीएसटी परिषद ने मकान पर जीएसटी दरों में कटौती कर खरीदार और बिल्डर दोनों को बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही परिषद ने किफायती मकान की परिभाषा भी तय की है। इसके अनुसार गैर महानगरों में 90 वर्गमीटर और महानगरों में 60 वर्गमीटर तक कारपेट एरिया के आवासीय मकानों को किफायती मकान माना जाएगा। जीएसटी परिषद का यह कदम तो काफी अच्छा है लेकिन महानगरों और गैर महानगरों में किफायती मकानों के लिए मूल्य के हिसाब से एक जैसी सीलिंग अच्छा कदम नहीं है। 45 लाख रुपये तक कीमत के मकानों को महानगर और गैर महानगर के लिए किफायती मकान मानना सही नहीं है। महानगरों के लिए 45 लाख रुपये की सीमा को और बढ़ाना चाहिए। यह सीमा किफायती मकानों में एक बड़ी बाधा बन सकती है। किफायती मकानों की परिभाषा में इस अव्यवहारिकता को दूर कर दिया जाए तो जीएसटी दरों में कटौती से रियल एस्टेट उद्योग के वास्तव में अच्छे दिन आ सकते हैं।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।